THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI B. P. MAURYA): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House when received.

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को चावल की सप्लाई करने में हुई प्रगति

1742. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक लाख टन चावल देने का वायदा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). 1 लाख टन चावल अधिप्राप्त करने के लक्ष्य के प्रति 50,000 मीटरी टन केन्द्रीय पूल को देने का वायदा किया गया था। राज्य सरकार ने अब तक 40,000 मीटरी टन चावल अधिप्राप्त किया है और केन्द्रीय पूल को कोई मात्रा पेश नही की गई है।

Survey regarding prostitution

1743. SHRI M. S. UPRTY: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey of the wide-spread prostitution in the country;

(b) if so, the number of rescued women, Statewise during last two years; and

(c) the steps Government have taken to remove it and to improve the social standard of society?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No all India survey has been conducted.

(b) Does not arise.

(c) The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 was enacted to provide for measures to suppress the traffic, abolish the brothels and commercialised vide and is intended to be a supplement to the provisions of the Indian Penal Code.

In addition, the various economic, educational and social programmes in different sectors directly or indirectly aim at this end. The Association for Social Health in India, New Delhi, is also given financial assistance for voluntary effort towards preventive and rehabilitative services, etc.

खाद्य तेल का संकट

1744. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल के संकट ने उग्र रूप धारण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चालू वर्ष में अच्छी खरीफ फसल के बावजूद देश में तेल की सप्लाई और मूल्य की स्थिति कठिन है। इसका कारण यह है कि 1972–73 के दौरान तिलहनों के उत्पादन में भारी कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप स्टाक खत्म हो गया। सट्टे का व्यापार और विभिन्न स्तरों पर स्टाक की

जमाखोरी, सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि और विश्व की मंडियों में तेलों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि भी इसके कारण हैं। सरकार ने देश में वनस्पति तिलहनों और तेलों की उपलब्धि में सुधार करने और उनकी कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनमें ये शामिल हैं—विभिन्न तिलहनों, तेलों और चिकनाई का आयात करके यथासम्भव सप्लाई बढ़ाना, बिनौले की पिराई और चावल की भूसी के तेलों को प्रोत्साहन देना, वृक्ष मूलक गौण तिलहनों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देना, वनस्पति घी के निर्माण में विभिन्न वैकल्पिक तेलों का प्रयोग करके मूंगफली और सरसों के तेल के प्रयोग पर पाबंदी लगाना, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज जैसे पारम्परिक और अपारम्परिक तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना तथा बैंक ऋण और सट्टा व्यापार का नियमन करना। हाल ही ही में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सट्टा व्यापार और जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठायें।

दिल्ली के हरिनगर डिपो में दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों द्वारा हड़ताल

1745. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के हरि नगर डिपो के ड्राइवरों द्वारा 31 जनवरी 1974 को हड़ताल कर दिए जाने से दिल्ली मे बसों का यातायात ठप्प हो गया था ;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा ;

(ग) क्या ड्राइवर और कण्डक्टर प्रायः ऐसा करते रहते हैं जिससे बस यातायात अवरुद्ध हो जाता है; और

(घ) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है जिससे यातायात ठीक ढंग से चलता रहे और भविष्य में इस प्रकार कठिनाइयां उत्पन्न न हों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। परन्तु माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित तारीख तो बस सेवाओं में गड़बड़ी रही जो अधिकांश पश्चिम दिल्ली में और हरिनगर डिपो के कुछ इलाकों में हुई जो दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्ध द्वारा हरिनगर डिपो से सबद्ध कुछ चालकों को शाहदरा डिपो 2 की बदली के जारी किये गये आदेश के विरुद्ध उक्त डिपो के कुछ कर्मचारियों द्वारा धरना देने के कारण हुई।

(ख) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए अन्य डिपुओं से चलने वाली सेवाओं को मोड़ा गया।

(ग) जी, नही।

(घ) हड़तालों, कर्मचारियों में अनुशासन हीनता और निगम को वित्तीय घाटा रोकने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं जिसमें यह निर्धारित किया गया कि उन कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं दिया जायेगा जो बिना छुट्टी मांगे या उच्च अधिकारियों के स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहेगा। इसी तरह जहां कर्मचारी काम पर आया है परन्तु कोई ड्यूटी नहीं करता उसे वेतन संदाय अधिनियम के अधीन ऐसी अवधियों के लिए कोई वेतन देय नहीं होगा।